नईदुनिया

संपादकीय

पाक की गोलीबारी से उकसावे की चाल

पहलगाम *हमले के बाद जिस तरह भारत में आक्रोश है और सरकार पर कोई बड़ी कार्रवाई करने का जन-दबाव बन रहा है, उसे देखते हुए पाकिस्तान में घबराहट है। उसने घटना के बाद सीमा पर हवाई गश्ती और चौकियों पर सैनिक दस्ते बढ़ा दिए। हालांकि वह लगातार कह रहा है कि उस हमले में उसका कोई हाथ नहीं था, उसकी जांच की पेशकश भी कर रहा है, पर वहां की सेना जिस तरह बार-बार संघर्ष विराम का उल्लंघन कर रही है, उससे जाहिर है कि वह भारतीय सैनिकों को उकसाने की कोशिश कर रही है।*

पहलगाम हमले के बाद से वह चार बार गोलीबारी कर चुकी है। हालांकि आमतौर पर छोटे हथियारों से गोलीबारी की जाती है, तो उसका यही मतलब होता है कि दुश्मन देश सीमा पर अपने सैनिकों की मुस्तैदी का संकेत दे रहा है। बताने का प्रयास कर रहा है कि वह किसी भी तरह की चुनौती से निपटने को तैयार है। मगर पाकिस्तानी सेना साजिशन ऐसा करती है। अक्सर वह अपने प्रशिक्षित आतंकवादियों को भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने के मकसद से इस तरह गोलीबारी करती है। इस तरह वह अनेक बार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर चुकी है।

पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी से यह शक गहरा होता है कि उसकी साजिश में कहीं न कहीं उसका हाथ है। यह छिपी बात भी नहीं है कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने में मुख्य रूप से पाकिस्तानी सेना और वहां की खुफिया एजंसी का हाथ है। इसके अनेक प्रमाण मौजूद हैं। भारत सरकार अनेक आतंकी हमलों से जुड़े प्रमाण पाकिस्तान सरकार और अंतरराष्ट्रीय समुदाय को सौंप चुकी है।

मगर पाकिस्तान हर दस्तावेज को सिरे से खारिज करता रहा है। वह खुद दहशतगर्दी के गहरे जख्म झेल चुका है, पर इस पर नकेल इसलिए नहीं कस पाता कि वहां निर्णय करने का कोई व्यवस्थित तंत्र नहीं है। वहां की सेना ने सियासी हुकूमत के ऊपर अपना वर्चस्व बना लिया है। इसलिए सरकार के स्तर पर लिया गया कोई भी निर्णय सेना अपनी मर्जी से स्वीकार या अस्वीकार करती है। दरअसल, आतंकवाद को वहां की सेना ने अपना हथियार बना लिया है और उसका इस्तेमाल वह मुख्य रूप से भारत के खिलाफ करती रही है। ऐसा लगता है कि इसी से उसका वजूद बचा और बना हुआ है। वह भारत के खिलाफ आतंकी गतिविधियां चला कर उकसाने और सीमा पर तनाव बनाए रख कर पाकिस्तानी अवाम को बरगलाने में कामयाब होती रही है।

आतंकवाद और भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्ते पाकिस्तान सरकार को भी रास आते हैं। इस तरह वह बुनियादी समस्याओं की तरफ से वहां के लोगों का ध्यान भटकाने में कामयाब हो जाती है। पाकिस्तान पूरी तरह से विफल राष्ट्र है। उसकी माली हालत निहायत खस्ता हो चुकी है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं दुर्दशा झेल रही हैं। लोगों को दो जून की रोटी के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। उधर बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन रोज उसे गंभीर चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के साथ सीमा पर तनाव से बुनियादी समस्याओं पर कुछ समय के लिए पर्दा पड़ जाता है। मगर इस तरह वहां की सरकार बहुत लंबे समय तक अपनी कमजोरियों को ढंक कर नहीं रख सकती। फिर, चीन से उसे जो मदद मिल रही है, वह स्थायी नहीं है। अपना स्वार्थ सधते ही वह अपना हाथ खींच लेगा।

खेलो इंडिया में दिखेगा बिहार का दमखम

अजय पांडेय

विकास के साथ जिस सर्व-समावेशिता की बात आज विश्व बैंक से संयुक्त राष्ट्र तक हर मंच पर होती है, उसके लिए हो रहे प्रयास देश के संघात्मक ढांचे की नई चमक को जाहिर कर रहे हैं। इस लिहाज से सबसे दिलचस्प है खेलों की दिशा में राज्यों का शानदार प्रदर्शन। जिस आयोजन की आज पूरे देश में चर्चा है, वह है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। इस बार यह अहम आयोजन न सिर्फ बिहार में हो रहा है बल्कि प्रदेश के पांच शहरों में इससे जुड़ी खेल प्रतियोगिताएं हो रही हैं। ये शहर हैं- पटना, राजगीर, भागलपुर, गया और बेगूसराय।

बिहार जैसे सूबे में इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय खेल आयोजन के मायने गहरे और बहुस्तरीय हैं। कुछ दशक पहले तक बिहार वैसे राज्यों में शुमार होता था, जिसके विकास की संभावनाओं पर लगातार नकारात्मक तरीके से विचार किया गया। दरअसल, इस पूरे संदर्भ का आगाज 1980 के दशक में तब हुआ, जब जनसांख्यिकी और आर्थिक नीतियों के विश्लेषक आशीष बोस ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी। बोस ने इस रिपोर्ट में देश के चार बड़े राज्यों बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश को 'बीमारू' राज्य बताया। पर बीते दशकों में यह स्थिति लगातार बदली है। इस दौरान विकास को लेकर इन राज्यों के विकास का नया चरित्र उभरा है।

बात अकेले उस सूबे की करें जहां इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का मेगा आयोजन हो रहा तो यह इस सूबे की खेल संस्कृति और उस दिशा में हो रही प्रगति की ओर स्वभाविक तौर पर ध्यान ले जाता है। आज की तारीख में ऐतिहासिक विरासत, संस्कृति और बौद्धिक परंपराओं के लिए मशहूर बिहार खेल के क्षेत्र में नई पहचान बना रहा है। पिछले कुछ वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं की मेजबानी में बिहार का दमखम खासतौर पर दिखा है। बिहार की दृष्टि से यह बड़ा बदलाव है।

खेलों की मेजबानी में बिहार को प्राथमिकता मिलने के पीछे कई अहम कारण हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य की सरकार ने बीते दो दशकों में स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ट्रेनिंग सेंटर और आधुनिक खेल सुविधाओं के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। यही कारण है कि राजगीर को एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप की मेजबानी मिली। पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अब राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के लिए तैयार है। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर में भी नए स्टेडियम बनाए जा रहे हैं।

खेलों के आयोजन से बिहार जैसे राज्य की अर्थव्यवस्था को बहुआयामी लाभ मिल रहा है। दरअसल, जब कहीं भी राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता आयोजित होती है, वहां हजारों खिलाड़ियों, कोच, आयोजकों और दर्शकों का आगमन होता है। इससे होटल, रेस्तरां, परिवहन, लोकल मार्केट और पर्यटन स्थलों को बढ़ावा मिलता है। हाल ही में पटना में आयोजित राष्ट्रीय खेल आयोजन के दौरान होटल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में 40 फीसदी तक की वृद्धि दर्ज की गई, जिससे स्थानीय व्यापारियों को सीधा लाभ हुआ।

खेल आयोजनों से निजी निवेश को भी बढ़ावा मिलता है। खेलों को बढ़ावा देने वाले राज्य में कॉरपोरेट कंपनियां, स्पॉन्सर और खेल ब्रांड निवेश करने के लिए आकर्षित होते हैं। बिहार में अब कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेल ब्रांड अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, जिससे खेल उपकरण उद्योग, प्रशिक्षण संस्थान और अन्य संबंधित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इससे न केवल राज्य की जीडीपी को मजबूती मिलेगी बल्कि युवाओं के लिए करियर के नए विकल्प खुलेंगे।

राज्य में अब नियमित रूप से राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिससे बिहार के खिलाड़ियों को अपने ही राज्य में उच्चस्तरीय प्रतिस्पर्धा का अनुभव मिल रहा है। पहले उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और मौके के लिए दूसरे राज्यों में जाना पड़ता था, लेकिन अब पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा जैसे शहरों में खेल सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इससे बिहार के उभरते हुए एथलीटों को अपने घर के नजदीक विश्वस्तरीय कोचिंग और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने का अवसर मिल रहा है।

बिहार में खेल आयोजनों की सफलता से राज्य की वैश्विक पहचान भी बन रही है। स्वाभाविक तौर पर जब कोई बड़ा टूर्नामेंट आयोजित होता है तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया में उसकी चर्चा होती है। इससे बिहार की छवि आधुनिक, प्रगतिशील और खेल-समर्थक राज्य के रूप में बनती है। पहले बिहार को केवल प्राचीन संस्कृति और ऐतिहासिक स्थलों के लिए जाना जाता था लेकिन अब इसे खेलों की नई राजधानी के रूप में भी देखा जा रहा है।

खेल आयोजनों का एक बड़ा लाभ यह भी है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। बिहार पहले ही बौद्ध धर्म और ऐतिहासिक विरासत के कारण लाखों पर्यटकों को आकर्षित करता है। अगर राज्य में अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं नियमित रूप से आयोजित होती हैं, तो इससे यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी। खेल आयोजनों के दौरान पर्यटक न केवल मैच देखने आते हैं बल्कि वे स्थानीय बाजारों, हस्तशिल्प उद्योग और ऐतिहासिक स्थलों का भी भ्रमण करते हैं। इससे बिहार की पर्यटन अर्थव्यवस्था को मजबूत आधार मिलता है।

खेल आयोजनों से राज्य में स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का विकास भी तेज हो रहा है। खेल सुविधाओं के निर्माण, स्पोर्ट्स गियर मैन्युफैक्चरिंग, फिटनेस और कोचिंग सेंटरों की संख्या बढ़ रही है। बिहार सरकार ने खेल नीति 2023 के तहत खेल-केंद्रित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने का भी फैसला किया है, जिससे युवा उद्यमियों को खेल से जुड़े व्यापार में कदम रखने का अवसर मिलेगा।

अगर बिहार में खेलों के महत्वपूर्ण आयोजन इसी तरह होते रहे तो आने वाले वर्षों में यह राज्य देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक बन सकता है। इससे जहां खेल स्पर्धाओं से जुड़े रोजगार के अवसर और पर्यटन का विकास होगा बल्कि निवेश में वृद्धि आएगी और स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। इस तरह की बढ़त और अनुकूलताओं से बिहार की छवि तो सुधरेगी ही, राज्य को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक ब्रांड के रूप में स्थापित होने का भी मौका मिलेगा।

रेटपेयर्स की सक्रिय भागीदारी से ही अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति

डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

रेटपेयर्स से सीधा-सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरे में आती हैं। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरे में प्रमुखता से ला रही हैं। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

भगवान आज हमारी अर्थव्यवस्था भले विश्व की दस प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो व जीडीपी रैंकिंग में इस साल हम विश्व की तीसरी प्रमुख अर्थव्यवस्था बनने की तैयारी में हों पर अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास के लिए रेटपेयर्स की भागीदारी बढ़ाने की आज सबसे अधिक आवश्यकता है। फ्रीबीज के जमाने में केन्द्रीय वित्त सचिव अजय सेठ द्वारा एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए देश की आर्थिक वृद्धि के लिए रेटपेयर्स को प्रोत्साहित करना जरुरी बताया गया है।

दरअसल, एक ओर राजनीतिक दलों द्वारा लोक लुभावन फ्रीबीज सुविधाओं की घोषणाएं-दर-घोषणाएं की जा रही हैं तो दूसरी ओर देश को 2025 में जीडीपी रैंकिंग के अनुसार दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की चुनौती है। अर्थव्यवस्था का सीधा-सीधा गणित यह है कि एक तो करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रुप से कर के रुप में सीधे-सीधे आय सरकार को प्राप्त होती है तो दूसरी ओर सरकार अपनी विकास योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए उधारी से काम चलाने वाली स्थिति होती है जिसे हम बजट प्रस्तावों में उधारी के रुप में देखते हैं। तीसरा प्रमुख स्रोत रेटपेयर्स होते हैं, देश का सेविंग पूल इन्हीं से बनता है।

जहां तक आयकर का प्रश्न है तो आधार और पैनकार्ड के चलते अब आयकर के दायरे से कोई बच नहीं सकता। खासतौर से नौकरीपेशा या निश्चित पगार पाने वालों का तो आयकर सीधे-सीधे और बिना किसी छीजत के सरकार को प्राप्त हो जाता है। इसमें किसी तरह की चोरी की संभावना न के बराबर है। लगभग यही स्थिति जीएसटी के बाद देखने को मिल रही है और साल दर साल जीएसटी संग्रह में बढ़ोतरी भी हो रही है।

दरअसल, जब स्थानीय स्वशासन की परिकल्पना की गई थी तो उसके साथ यह भी था एक समय आते-आते यह संस्थाएं अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए सरकार पर निर्भर ना रहकर आत्मनिर्भर हो जाएंगी और इन संस्थाओं को सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। पर एक ओर यह सपना ही बनकर रह गया दूसरी ओर राजनीतिक दलों ने फ्रीबीज का ऐसा चलन चलाया कि रेटपेयर्स की भूमिका कम से कम होती जा रही है।

रेटपेयर्स का प्रयोग सबसे पहले 1845 में माना जाता है। रेटपेयर्स की भूमिका को हम इससे अच्छी तरह समझ सकते हैं कि न्यूजीलैण्ड सहित अनेक देशों में तो रेटपेयर्स अपने हितों की रक्षा के लिए एसोसिएशन बनाकर आगे आ रहे हैं। हमारे देश में हालात इससे विपरीत है। हमारे यहां पिछले कुछ सालों में रेटपेयर्स की सहभागिता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। केन्द्रीय वित सचिव अजय सेठ के अनुसार संभवत: यही चिंता का कारण बन रहा है।

रेटपेयर्स से सीधा-सीधा अर्थ सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में जो बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है उससे विकास या बेहतर सेवाओं के लिए राशि प्राप्त की जा सके। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, सार्वजनिक परिवहन या इसी तरह की सेवाएं इसके दायरे में आती हैं। चुनावी वादों के चलते सरकार द्वारा बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि को कम-ज्यादा पर फ्रीबीज के दायरे में प्रमुखता से ला रही हैं। पेंशन योजनाएं और फ्री राशन, सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं, सीनियर सिटीजन व अन्य को राहत या अन्य दूसरी इसी तरह के निर्णय रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी को सीमित करते हैं।

लोकतंत्र में समान अवसर और आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए अनुदानित योजनाओं का संचालन संवेदनशील और लोकहितकारी सरकार के लिए आवश्यक है। पर इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि सार्वजनिक सुविधाओं के लिए सरकार द्वारा जो राशि कर या अन्य रुप में प्राप्त की जाती है वह नहीं मिले और उसका भार भी ईमानदार कर दाताओं पर पड़े तो यह किसी भी हालत में सही नहीं है। सरकार को सक्षम और कम सक्षम में अंतर करके चलना होगा। केन्द्रीय वित सचिव की मंशा कहीं ना कहीं यही होगी कि फ्रीबीज के कारण जो रेटपेयर्स की अर्थव्यवस्था में भागीदारी दिन-प्रतिदिन कम हो रही है उसपर ध्यान देना आवश्यक है।

इसमें दो राय नहीं कि समाज की मुख्यधारा से वंचित लोगों को सहायता दी जाए पर यह नहीं होना चाहिए कि मुख्यधारा से वंचित के नाम पर आर्थिक दृष्टि से सक्षम लोगों या परिवारों को भी यह सुविधाएं दी जाए। इससे होता यह है कि जो आम करदाता है वह तो अपने आपको ठगा महसूस करता ही है, कहीं ना कहीं समाज में गैप भी बढ़ता है। आर्थिक विकास में जो जनभागीदारी होनी चाहिए वह भी बाधित होती है। ऐसे में फ्रीबीज की राजनीति के बीच रेटपेयर्स की भागदारी को भी बढ़ाना होगा जिससे अर्थव्यवस्था का मल्टिपल विकास संभव हो सके। आज के लाभार्थियों को भी अर्थव्यवस्था के व्यापक हित में समझना होगा।

आजकल

मार्क कार्नी का नया कनाडा

कनाडा के आम चुनावों में मार्क कार्नी के नेतृत्व में लिबरल पार्टी की जीत भारत से संबंधों में सुधार के नजरिये से बेहद महत्वपूर्ण है। चुनाव से पूर्व और चुनाव के दौरान कार्नी कहते रहे हैं कि आने वाले समय में भारत से बेहतर रिश्ते बनेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की दुराग्रह और पृथक्तावादियों के दबाव के चलते भारत कनाडा संबंध अपने सबसे बुरे दौर में पहुंच गए थे। कार्नी की जीत से उम्मीद जगी है कि दोनों देशों के संबंध फिर से पटरी पर लौटेंगे।

दरअसल, एक अपरिपक्व राजनेता की तरह जस्टिन ट्रूडो ने निज्जर प्रकरण को जिस तरह तूल दिया, उसके चलते दोनों देशों के संबंध बेहद खराब स्थिति में पहुंचे। हालांकि, भारत सरकार ने निज्जर प्रकरण में हाथ होने के दावों का दृढ़ता से खंडन किया था। लेकिन इसके बावजूद दोनों देशों के राजनीतिक, आर्थिक संबंध और लोगों के आने-जाने का उपक्रम बुरी तरह प्रभावित हुआ था। नि:संदेह, कार्नी का फिर सत्ता में लौटना संबंधों में सुधार का स्पष्ट संकेत है। वे अपने पूर्ववर्ती के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित आर्थिक विशेषज्ञ, व्यावहारिक राजनेता और बयानों में संतुलन रखने वाले व्यक्ति हैं। दरअसल, हाल के चुनावों में उनका 'मजबूत कनाडा, मुक्त कनाडा' का नारा खूब चला। ट्रंप के टैरिफ वार और बार-बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने के बयानों ने कनाडा के लोगों में असुरक्षा का भाव भर दिया।

कनाडाई जनमानस को पढ़ने में सक्षम कार्नी ने इस मुद्दे को हथियार बनाकर पार्टी की सत्ता में वापसी करा दी। अन्यथा कुछ समय पूर्व पार्टी के पराजय को लेकर दावे किए जा रहे थे। दरअसल, उन्होंने कनाडा को मजबूत करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बहाल करने की बात कही ताकि घरेलू स्थिरता को मजबूत किया जा सके। निश्चित रूप से कार्नी का यह दृष्टिकोण व्यापारिक, रणनीतिक व लोगों को जोड़ने की दृष्टि से भारत के लिये महत्वपूर्ण अवसर साबित होगा।

बड़ी कीमत चुकानी होती है युद्ध की

क्षमा शर्मा

पहलगाम में जिस तरह से धर्म पूछ-पूछकर, एक समुदाय के आतंकवादियों ने दूसरे समुदाय के लोगों की हत्या की, वह बेहद निंदनीय है। वह स्त्री जिसकी एक महीने पहले शादी हुई, वह जिसकी एक हफ्ते पहले शादी हुई और जान गंवाने वाले बाकी के लोग, उन्होंने किसका क्या बिगाड़ा था। कश्मीर में अरसे से इस तरह के हत्याकांडों को अंजाम दिया जा रहा है।

जब से यह हत्याकांड हुआ है, केंद्र की सरकार ने बहुत से कूटनीतिक कदम भी उठाए हैं, जिनमें सिंधु जल समझौते को रोकना, पाकिस्तानियों को देश से निकालना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बारे में आगाह करना आदि बातें शामिल हैं। हालांकि, बहुत से दल और लोग सरकार की देरी पर सवाल उठा रहे हैं, उकसा रहे हैं। सरकार अगर सोच-समझकर निर्णय लेना चाहती है तो इसमें गलत क्या है।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक तरफ तो कहा जा रहा है कि अभी के अभी फौरन युद्ध चाहिए। दूसरी तरफ लोग हर बात के लिए सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ये चाहते हैं कि सरकार इनकी मांग पर युद्ध शुरू कर दे। पाकिस्तान और भारत के बयानवीर तरह-तरह के बयान दे रहे हैं। इस कठिनाई के समय किसी के भी द्वारा राजनीति की रोटियां सेकना बंद किया जाना चाहिए।

जब से इराक, अमेरिका युद्ध का लाइव प्रसारण शुरू हुआ, तब से मीडिया के लिए युद्ध बहुत आकर्षक हो चला है। आखिर जो देश युद्ध में फंसे होते हैं, उनके घरेलू मोर्चे पर क्या होता है। पहली बात तो महंगाई इतनी बढ़ जाती है कि उसकी कल्पना करना मुश्किल है। काले बाजारियों की बन आती है। जरूरी चीजें रातों-रात बाजार से गायब हो जाती हैं। उन्हें मनमाने दामों पर बेचा जाता है। दवाइयों की बहुत किल्लत हो जाती है। आवागमन पर इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के तौर पर जैसे ही पहलगाम में लोगों को मारा गया, एयरलाइंस ने अपने किराए छह गुने बढ़ा दिए। सरकार ने उनसे किराया कम करने को कहा भी लेकिन एयरलाइंस कम्पनियां नहीं मानीं। जबकि कश्मीर की घटना के बाद कोई युद्ध नहीं शुरू हो गया था। ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि लोग इस डर से कि कहीं युद्ध हुआ अगर वक्त पर कोई सामान लड़ाई के कारण नहीं मिला तो भारी मात्रा में खरीददारी कर रहे हैं। लेकिन ऐसा वे ही कर सकते हैं, जिनकी जेब में अतिरिक्त पैसा है। जो रोजमर्रा की कमाई पर निर्भर हैं, वे क्या करेंगे। कोरोना के वक्त भी ऐसा ही हुआ था। महंगाई की मार हर वर्ग को झेलनी पड़ती है। उस मध्यवर्ग को तो ज्यादा ही जो इन दिनों फौरन युद्ध का समर्थन कर रहा है। आखिर युद्ध के वक्त सरकारों के पास पैसा कहां से आएगा, टैक्स के रूप में हमारी जेब से ही। सरकारों के पास अपनी आय तो होते नहीं। लोगों पर टैक्स लगाकर ही वह अपनी आय बढ़ाती है।

जो देश भी युद्ध में फंसते हैं, उनकी आर्थिकी तबाह हो जाती है। तमाम दुनिया के देश और संस्थाएं सक्रिय हो जाती हैं। वे हर तरह से अपने लाभ-हानि का गणित बैठाते हैं। हथियारों के सौदागरों के लिए कोई भी लड़ाई, अपने मुनाफे का स्वर्णिम अवसर होता है। पश्चिमी देशों का दोमुखी रवैया जगजाहिर है। पाकिस्तान के संदर्भ में अक्सर हमने यह होते देखा है, जहां पाकिस्तान को वे खुद आतंकवाद से पीड़ित बताते रहे हैं। अब वे अभी उकसा रहे हैं, बाद में गायब भी हो जाएंगे। आपकी आफत है, आप खुद निपटिए। विदेशों में शांति फैलाने वाली संस्थाओं के एक हाथ में शांति का फूल होता है तो दूसरे में हथियार। यकीन न हो तो नोबेल पीस प्राइज देने वालों को देख लीजिए। उनकी कम्पनियां दुनिया के मारक हथियार बनाती हैं। इतनी ही शांति की चिंता है तो हथियार बनाना बंद क्यों नहीं कर देते।

वर्ष 1965, 1971, 1999 में हमने पकिस्तान से तीन युद्ध लड़े हैं। हर बार जीते हैं, बल्कि बांग्लादेश बनवाकर अक्सर हम अपनी पीठ थपथपाते रहे हैं कि पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए, लेकिन अब बांग्लादेश क्या कर रहा है, यह देखा जाना चाहिए। एक बार मशहूर लेखक सलमान रुश्दी ने कहा था कि आप चाहे पाकिस्तान के कितने भी टुकड़े कर दें लेकिन वे एक विशेष विचारधारा से संचालित होते हैं, इसलिए रहेंगे आपके शत्रु ही।

इन तीनों युद्धों में विजय पाकर भी अखिर हमने क्या पाया। सिवाय इसके कि समझौते करने पड़े। करगिल युद्ध के दौरान एक बार बताया गया था कि इसे जीतने में बोफोर्स तोपों की बड़ी भूमिका थी। उसी में पढ़ा था कि तोप के एक गोले की कीमत सत्तर हजार रुपये थी। बताइए कि आज क्या होगी। जिन मिसाइलों को हम हवा में उड़ते देखकर रोमांचित होते हैं, उनमें से एक-एक मिसाइल की कीमत कितनी होती है, जरा पता कर लीजिए। आज के दौर में किसी युद्ध को आसानी से जीता नहीं जा सकता, जीत भी लें तो अक्सर जीते हुए स्थान उस देश को वापस लौटाने पड़ते हैं, जैसे कि हमें 1965 में करना पड़ा था। तमाम देश भारी दबाव डालते हैं। आज के युग में कोई भी लड़ाई स्थानीय नहीं है। उसमें तमाम वैश्विक शक्तियों की भागीदारी होती है। यह भी सच है कि किसी को भी धरती के नक्शे से मिटाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा होता तो रूस ने यूक्रेन को निगल लिया होता।

हर बार लड़ाई में अपने-अपने हितों के आधार पर तमाम देश पक्ष-विपक्ष चुनते हैं। तुर्किए को ही देख लीजिए। जैसे ही भारत-पाकिस्तान युद्ध की बात चली, वहां के विमान युद्ध की सामग्री लेकर पाकिस्तान आ पहुंचे। ये पश्चिमी देश भी दो देशों को युद्ध में फंसाकर, अपने हित साधने के लिए आ जाएंगे। इसी आधार पर समर्थन और विरोध करेंगे।

आज कोई दो ध्रुवीय दुनिया भी नहीं है। वर्ष 1971 में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना मशहूर सैवेंथ फ्लीट भेजा था तो रूस ने भी हमारी मदद के लिए अपने युद्धपोत भेज दिए थे।

यहां यह कहने की कोई कोशिश नहीं की जा रही कि पाकिस्तान को आतंकवाद को प्रायोजित करने का सबक न सिखाया जाए। लेकिन युद्ध में कूदने से पहले इसका वास्तविक आकलन करना जरूरी है। चैनल्स का या सोशल मीडिया का युद्ध उन्माद भी भरोसे लायक नहीं है। इनमें से किसी को वास्तविक लड़ाई नहीं लड़नी है। इनके लिए लड़ाई भी एक बड़ा इवेंट है।

सरकार सोच-समझकर निर्णय कर रही है, जो बिल्कुल ठीक है। आतंकवादियों को सबक सिखाना जरूरी है, जिसके लिए पुख्ता रणनीति चाहिए। यह भी जरूरी है कि देश एक सुर में बोले, एक रहे। युद्ध कोई स्वादिष्ट परांठा नहीं है, जिसे चटनी, अचार, रायते के साथ खाकर आप चैन की नींद सो सकते हैं। अगर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई देश युद्ध करता है, निरपराध लोगों को मारता है तो जवाब देने का अधिकार दूसरे देश को है। आतंकवाद को सख्ती से निपटाना होगा, जिससे कि फिर कोई निरपराध जान न गंवाए।